

प्रेषक,

राधा स्तूडी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तरांचल ।

वित्त अनुभाग-3

दैहरादून दिनांक 2-अगरत, 2005

**विषय:-** राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में रायिलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश रांख्या -3 - 728 / दस - 901 - 98, दिनांक 10-7-1998 के प्रथम प्ररतार में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह रोगानिकृत होगा वहीं सरकार उसके रोगानिवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी । उक्त शासनादेश दिनांक 10-7-98 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या रीतों से ग्रहण करे या उन्हीं परिस्थिति में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर रीतों गतीं से जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाएं । उपर्युक्त उल्लिखित विधि स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" जहाँ पेंशन व्यवस्था लागू की गयी है, परन्तु उक्त आदेश दिनांक 10-7-98 में कठिप्रय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है । जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम/निगम" के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी । इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10-7-98 की व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम" में नहीं । अतएव शासनादेश में जहाँ लाभों "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से निलोगित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द प्रतिस्थापित माना जाए ।

2. "स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50प्रतिशत से अधिक की व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है । स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के समविधिक निकाय समिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय

संस्थाये/बैंक शामिल नहीं होंगे । इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है ।

3. शासनादेश संख्या सं0-3-728/दस-98-901-98, दिनांक 10-7-98 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

भवदीय  
(राधा रत्नाली)  
सचिव,

संख्या ३०७XXVii(3) / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, देहरादून ।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
4. निदेशक, समरत प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव,
5. निदेशक, कोषागार वित्त एवं सेवायें, उत्तरांचल ।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशक, एन०आई०सी० देहरादून ।

आज्ञा से  
(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव

1208050010